

श्रमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I---खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

म ः 61]

नई विन्त्रो, बृहस्पतिवार, स्रश्रेल 29, 1971/वैद्याल 9, 1893

No. 641

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 29, 1971/VAISAKHA 9, 1833

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दो जाती है जिससे कि यह भ्रलग मंकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (Department of Industrial Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 29th April 1971

No. 5(17)/70-A.E.Ind (I).—A Commission was constituted on the recommendations of the Supreme Court vide Resolution No. 5(17)/70-A E.Ind.(I). dated the 27th May, 1970 for the purpose of recommending the fair selling prices of the three makes of cars manufactured in the country namely. Ambassador, Fiat and Standard Herald under the Chairmanship of Shri Sarjoo Prasad Singh, Retired Judge of the Patna High Court

2. The Commission was to submit its report within a period of four months from the date of its constitution. The Commission started its work on the 1st June, 1970. As the Commission could not complete its work within the stipulated period, it approached Government for extension of its term by three months. Accordingly, a petition was moved before the Supreme Court reduciting the approval of the Honble Court for extending the term of the Commission by a period of three months from 1st October, 1970 to 31st December, 1970. The Supreme Court granted the extension asked for. Accordingly Government decided to extend the term of the Car Prices Inquiry Commission upto 31st December, 1970 vide Resolution No 5(17)/70-A.E.Ind.(1), dated the 4th November 1650.

- 3. The Commission again approached Government to extend its term by a further period of 2 months *i.e* from 1st January, 1971 to 28th February, 1971, since it could not complete its work by the 31st December, 1970. Accordingly, a petition was moved before the Supreme Court requesting the approval of the Hon ble Court for the extension of the term of the Commission *i.e.* from 1st January, 1971 to 28th February, 1971. The Supreme Court granted the extension asked for. Accordingly, Government decided to extend the term of the Car Prices Inquiry Commission upto 28th February, 1971 vide Resolution No. 5(17)/70-A E.Ind-(I), dated the 25th January, 1971.
- 4. The Commission approached Government once again to extend its term by a further period of one month ie from 1st March, 1971 to 31st March, 1971, since it could not complete its work by 28th February, 1971. Accordingly, a petition was moved before the Supreme Court, requesting the approval of the Hon'ble Court for the extension of the term of the Commission by a further period of one month i.e. upto 31st March, 1971. The Supreme Court has granted the extension asked for.
- 5 In view of this, Government decided that the term of the Car Prices Inquiry Commission be extended upto 31st March, 1971.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

S. K. SAHCAL, Jt Secy.

श्रौद्योगिक विकास तथा श्रांतरिक व्यापार मंत्रालय

(श्रोद्योगिक विकास विभाग)

संकल्प

मई दिल्ली, 29 भ्रप्रैल, 1971

- सं० 5(17) 70-ए०ई० इ०ड (1).—उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर देश मे निर्मित की जाने वाली तीन मैकों की कारों जैसे एम्बासेडर, फिएट तथा स्टैंडर्ड हैराल्ड के उचित विक्रय मूल्य की सिफारिश करने के लिए पटना उच्च न्यायालय के श्रवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री सरजू प्रसाद सिह् की श्रध्यक्षना में एक श्रायोग संकल्प सं0 5(17)/70-ए0ई0इण्ड 0(1) दिनांक 27 मई 1970 के द्वारा गठित किया गया था।
- 2. श्रायोग को अपने गठन की तिथि से चार महीने की श्रविध के अंदर अपना प्रतिबेदन प्रस्तुत करना था। श्रायोग ने श्रपना कार्य 1 जून 1970 से प्रारम्भ किया। चूंकि श्रायोग निर्धारित श्रविध में श्रपना कार्य पूरा नहीं कर सका अतः इसने सरकार से अपना कार्यकाल तीन महीने तक और बढ़ाने के लिए कहा। इसके श्रनुसार उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया गया। जिसमें श्रायोग द्वारा श्रपने कार्यकाल को 1 श्रक्तू र 1970 से 31 दिसम्बर 1970 तक की तीन महीने की श्रविध बढ़ाने के लिए श्रदालत से स्वीकृति मांगी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। जिसके फलस्वरूप सरकार ने कार मूल्य जांच श्रायोग का कार्यकाल संकल्प संग्ठ 5(17)/70-ए १६०इण्ड (1) दिनाक 4 नवस्बर 1970 के द्वारा 31 दिसम्बर 1970 तक बढ़ा देने का निश्चय किया।

- 3. श्रायोग ने श्रपने कार्यकाल को पुन: दो महीने श्रयान् 1 जनवरी 1971 से 28 फरवरी 1971 तक श्रौर बढ़ाने के लिए भरकार में कहा क्योंकि इनका कार्य 31 दिसम्बर 1970 तक पूरा नहीं हो सका था। तदनुसार उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया गया जिसमें श्रायोग के कार्यकाल को श्रयात् 1 जनवरी 1971 से 28 फरवरी 1971 तक बढ़ाने के लिए स्वीकृति मांगी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने श्रविध बढ़ाने की मजूरी दे दी। फलस्वस्प सरकार ने कार मृत्य जांच श्रायोग के कार्यकाल को संकल्प स0 5'(17)/70-ए0ई 0इण्ड (1) दिनांक 25 जनवरी 1971 के द्वारा बढ़ाने का निश्चय किया।
- 4. श्रायोग ने सरकार ने श्रपने कार्यकाल को पुन एक महीने श्रर्थात् 1 मार्च 1971 से 31 मार्च 1971 तक श्रौर बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि इनका कार्य 28 फरवरी 1971 तक पूरा नहीं हो सका था । तदनुसार उच्चतम न्यायालय ने निवेदन किया गया जिसमें श्रायोग के कार्यकाल को एक महीने श्रर्थात् 31 मार्च 1071 तक की श्रौर अवधि बढ़ाने की स्वीकृति मांगी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने श्रवधि बढ़ाने की मंजूरी दे दी।
- 5. इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निश्चय किया कि कार मूल्य जाच आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 1971 तक बढ़ा दिया जाए।

ग्रादेश

श्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी आए तथा इसे सर्वेसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० के० सहगल, संयुक्त सन्तिय ।